**Dereservation of leather goods**

3687. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several leather products, at present reserved for exclusive production in the Small Scale Sector have been thrown open by Government to large industries and even foreign companies with a view to increasing exports; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES) AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P.J KURIEN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**Filling up of vacant posts reserved for SC/ST in PSU**

3688. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes particularly in Group A & B posts to be filled up in different Public Sector Undertakings;

(b) the reasons for not filling up the vacancies so far;

(c) the steps taken or proposed to be taken by Government to fill up these vacancies; and

(d) by when these vacancies are likely to be filled up?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES) (SHRI P.K. THUNGON): (a) to (d) 4428 vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes were lying vacant in Group A and Group D posts in various Public Sector Undertakings as on 31.3.91. 3452 reserved vacancies have already been filled in as on 30.9.92. The Process of recruitment is still continuing. The Public Sector Undertakings have been advised from time to time to make vigorous efforts to fill up the backlog vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Various steps have been taken to ensure proper representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Public Sector Undertakings, such as relaxation in age limit, concessions in examination fees, reimbursement of travelling expenses for attending interviews, separate interview for candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, pre-recruitment training, inclusion of a member belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes in DPC/Selection Committee etc. Dereservation of reserved vacancies in direct recruitment has been banned *w.e.f.* 1st April, 1989 in Public Sector Undertakings.

**खादी और ग्राम उद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग**

3689. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी और ग्राम उद्योग आयोग में घपलेबाजी को रोकने तथा इसके कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा-शर्तों में सुधार के लिए सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान गठित किए गए आयोगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन आयोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की प्रमुख बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने के कारण क्या है?

**उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (पी॰) जे॰ कुरियन)**: (क) सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग

आयोग (के०बी०आई सी०) में गड़बड़ी की जांच करने तथा इसके कर्मचारियों के वेतनमानों तथा सेवाशर्तों में सुधार करने के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी आयोग का गठन नहीं किया है। तथापि, विभिन्न स्वतंत्र खादी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने के लिए श्री के० सी० सौधिया की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) में दिए गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

**उत्तर प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले**

3690. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के कुछ और जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले घोषित करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही):** (क) उत्तर प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के नाम निम्नलिखित हैं:

अल्मोड़ा, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, चलिया, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बुलन्दशहर, चमोली, देवरिया, एटा, टिवा फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोण्डा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, उन्नाव, उत्तरकाशी, कानपुर देहात, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल, शाहजहांपुर, सीतापुर और सल्तानपुर।

(ख) जी, नहीं,

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश में कम औद्योगिकृत क्षेत्रों का औद्योगीकरण करने के लिए केन्द्र सरकार विकास केन्द्र योजनात पर कार्य कर रही है। इस योजना के अधीन उत्तर प्रदेश को 8 विकास केन्द्र आवंटित किये गये हैं जिनमें से 7 विकास केन्द्र झांसी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, इटावा, बुलंदशहर, जौनपुर और पौड़ी गढ़वाल नामक पिछड़े जिलों में हैं। विकास केन्द्रों में आधारभूत सुविधाएं जुटायी जाएंगी ताकि उद्योग इन क्षेत्रों की ओर आकृष्ट हों, इस योजना का कार्यान्वय आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया जाएगा।

**Low capacity utilisation by PSU**

3691. SHRI KAMAL MORARKA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of Public Sector Units are not utilising optimum capacity;

(b) if so, the names of Public Sector Units which are using less than 50 per cent of their capacity during the first half of 1992-93;

(c) the reasons for low capacity utilisation;

(d) whether Government have issued any guidelines/instructions for making optimum use of capacity; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES) (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (e) During 1990-91, upto which period only information is available, there were 47 public sector units where capacity utilisation was less than 50%. Enterprise-wise capacity utilisation figures are given in the Statement at page S-137 to S-155 of the Public Enterprises Survey 1990-91 Volume-I, which was placed before the Parliament on 5.3.1992. Improvement in capacity utilisation is a part of the total performance improvement measures that the Government have taken up. These measures are enumerated at P-115 of the Volume referred to above. Besides these the Government have also issued guidelines to PSEs for the need for diversification, production planning, avoiding unilateral derating of capacity,